

दैनिक

पुष्पांजली दुड़े

नई सोच नई पहल

गवालियर, 24 नवम्बर शुक्रवार 2023



पृष्ठ: 8 मूल्य: 2 रुपए

गवालियर: वर्ष: 4 : अंक:16

राहुल गांधी को पनौती और जेबकरते वाले बायान पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस तो मलिकार्जुन खरगे ने कही ये बात



कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे ने गुरुवार (23 नवंबर) को पार्टी नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग से नोटिस मिलने पर कहा कि हम तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया। मलिकार्जुन खरगे

ने कहा, राहुल गांधी मिले नोटिस का हम समान करेंगे। नोटिस को ढेंडों। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी तुष्टिकरण कर रही है। दरअसल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्टी मोदी और जेबकरते वाली टिप्पणी को लेकर कारण तभी आयोग ने राहुल गांधी से चुनावार (25 नवंबर) की तारीख नोटिस पर जवाब देने को कहा है। उन्होंने विश्व कप के फाइनल मैच और एंडर्सनिया से भारत की बाद ये टिप्पणी की थी। स्टेडियम में पीएम मोदी भी मैच के दौरान मौजूद थे।

राहुल गांधी ने क्या कहा था-राहुल गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, पीएम का मतलब पार्टी मोदी है। मोदी कभी-कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं। वो अलग बात है कि हरवा दिया। इसको लेकर ही बीजेपी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग से चुनाव को शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी।

बीजेपी ने चुनाव आयोग से क्या कहा है-बीजेपी नेता गांधी मोहन दास अग्रवाल और ऑपम पाटक सहित प्रतिनिधिमंडल में शामिल अव्य नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। आयोग के साथै जान में पार्टी ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो क्योंकि उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।

राजौरी एनकाउंटर के बीच स्थानीय लोगों से पाकिस्तानी आतंकी की बातचीत का वीडियो वायरल



जम्मू-कश्मीर के राजौरी में मूठभेड़ के बीच एक पाकिस्तानी आतंकी का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसे स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए और कथित तौर पर खाना मांगते हुए देखा जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में सुश्वास अधिकारियों ने आतंकी का वीडियो जारी किया है, जिसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपलोड किया है। बता दें कि राजौरी एनकाउंटर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मार गया है और इसमें के चार जवान शहीद हो गए हैं। आतंकी का नाम कारी बताया गया है। वीडियो में पांच लोग दिख रहे हैं, जिनमें तीन महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। उनमें से एक शख्स को आतंकी कारी के रूप में बताया गया है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जारी वीडियो में आतंकी गारीजी में सुरक्षाकर्ता के साथ मूठभेड़ शुरू होने से फले स्थानीय लोगों के साथ आतंकी करते हुए देखा जा रहा है। बुधवार को आतंकियों ने रात भर के विराम के बाद गुरुवार करने की अनुरोध चाली याचिका पर गुरुवार (23 नवंबर) सुनवाई की ओरपुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। गांधी पर पीड़ितों के मातापिता के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया मच एस्स पर साझा कर पीड़ितों की पहचान उत्तरांश करने के लिए अपने जवाब दाखिल करने के लिए अधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि मारा गया आतंकी डांगरी और कंडी हूलों के मुख्य सामिजरक्ती माना जाता है। प्रकरा ने कहा कि कारी को क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए भेजा गया था और वह 'इमोवाइज्ड एंडरसोनेसिव डिवाइस' बनाने में माहिर था। इस साल जनवरी में दांगरी में हुए हमले में सात लोग मरे गए थे।

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का 96 साल की उम्र में निधन



सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी का गुरुवार (23 नवंबर) को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। आधिकारिक स्रोतों ने यह जानकारी दी। आधिकारिक स्रोत के बाहर से बताया कि नायामूर्ति बीवी को बढ़ती उम्र संबंधी बीमारियों के कारण कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज लगभग सवा 12 बजे उनका निधन हुआ। सूत्र ने कहा, 'उनका शब्द परन्तरियां में शिथ उनके आवास वापस लाया जा रहा है। पतनमतिष्ठा जुमा मस्जिद में कल (24 नवंबर को) अधिविरा रस्म पूरी की जाएगी।

फातिमा बीवी के बारे में जानें-फातिमा बीवी का करेल के पतनमतिष्ठा जिले में अप्रैल 1927 में जन्म हुआ था। उन्होंने 'कैथेटिक ट्वीट हीं स्कूल' से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर तिरुवनंतपुरम स्थित न्यूरिंगटी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थित विधि महाविद्यालय से कानून की डिग्री ली और 1950 में वकील के रूप में पंजाकण कराया। इसके बाद उन्हें 1958 में केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं में मुसिक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 1968 में अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में प्रवेत्त किया गया था और 1972 में मुख्य न्यायिक सेवाओं में बीजेपी पर भी अधीनस्थ न्यायाधीश बनी और 1980 में उन्हें अध्यकर अपीलीय न्यायाधीश के न्यायिक सदस्य के रूप में प्रवेत्त किया गया। उन्हें 1983 में केरल हाई कोर्ट में प्रवेत्त किया गया था और अगले ही साल वह वहां स्थायी जज बन गई।

विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही केंद्रीय एजेंसियां 2024

चुनाव के बाद बीजेपी के पीछे पड़ जाएंगी: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार (23 नवंबर) को दावा किया कि जो केंद्रीय एजेंसियां चर्माना में विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं वे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के पीछे पड़ जाएंगी। उन्होंने यह भी बोला कि बीजेपी पर सीएम ममता बनर्जी का निशाना - सीएम ममता ने पार्टी कार्यकार्ताओं से कहा, तंतान में विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही कीदीय एजेंसियां 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी के पीछे पड़ जाएंगी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार

आरक्षण खत्म करना चाहती है और वह इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा, बीजेपी भी



अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के खिलाफ हम उठे

ओबीसी कोटा के जरिए इस सिस्टम के तहत लायेंगे।

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया भगवाकरण करने का आपेष-मुख्यमंत्री ने यह भी आपेष लगाया कि मेट्रो रेलवे स्टेशनों से लेकर क्रिकेट टीम तक देश का भगवाकरण करने की कोशिशें जोगे पर चल रही हैं। उन्होंने कहा, भगवाकरणों से लाया जाता है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी केंद्र पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में होता तो टीम

रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में तेजी से हो रहा निवेश- ममता बनर्जीपश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में यात्रा की तस्करी के आरोपों को लेकर भी उन्होंने बीजेरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में तस्करी के लिए गांवों को यूपी समेत विभिन्न राज्यों से लाया जाता है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में विकास होता है लेकिन हम उसे निवेश के स्थान के रूप में विकसित हो रहा है।

निजी स्कूल के बैडमिंटन कोच की शर्मनाक हत्या!

लड़की से मांगी न्यूट तस्वीर, पुलिस ने किया गिरफ्तार

तमिलनाडु में कोयबट्टर सेंटरल मिलिया पुलिस ने गुरुवार (23 नवंबर) को एक प्राइवेट स्कूल के बैडमिंटन कोच को गिरफ्तार किया है। आपोनी कोच ने छात्रों से वॉटसेप पर अपनी नाम तस्वीरें भेजने को कहा कि जनहित याचिका पर कांग्रेस नेता को अभी तक कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के वकील ने कहा कि संबंधित पोस्ट के बाद बीजेपी की अकांट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। आपोनी कोच ने यह अपनी नाम तस्वीर तस्वीर करने के लिए अपनी सामान्य तस्वीर भेजी थी। इसके बाद उन्होंने न्यूट तस्वीरें देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने देश की तस्वीरें दिया। पीड़ित ने मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध की।

राहुल गांधी का अकांट अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। आपोनी कोच ने यह अपनी नाम तस्वीर तस्वीर करने के लिए अपनी सामान्य तस्वीर भेजने को कहा। हालांकि, लड़की ने उन्होंने न्यूट तस्वीरें देने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़की ने इस बात की सूचना अपने माता-पिता को दी, जिन्होंने बुधवार (22 नवंबर) की शाम को केंद्रीय मरिलां पुलिस निरीक्षक बाडिवकरसी के पास शिकायत दर्ज कराई।

राजस्थान में कभी भी नहीं होगी गहलोत सरकार की वापसी, पीएम मोदी ने फिर किया ऐलान

प्र

संपादकीय दवा के दर्द

यह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यथित करने वाली स्थिति है कि जिन जनसंरोक्तारों से जुड़े मुद्दों को सरकार को प्राथमिकता के आधार पर संवेदनशील ढंग से सुलझाना चाहिए, उन पर कोर्ट को पहल करनी पड़ रही है। ऐसे तमाम मुद्दों के साथ अब ऑनलाइन दवा बिक्री का मुद्दा भी जुड़ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सख्त लहजे में कहा कि सरकार के लिये यह आखिरी मौका है। वह आठ हफ्ते के बीच ऑनलाइन दवा बिक्री नीति बनाए। लंबे समय से मुद्दा लटकाने से क्षुध्य कोर्ट ने चेताया कि यदि सरकार ने नीति समय पर नहीं बनायी तो इस विभाग को देख रहे संयुक्त सचिव को आगामी चार मार्च को अदालत में जवाब देने आना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिशी पुष्करणा की पीठ ने नाराजगी जतायी कि इस नीति को बनाने के लिये सरकार के पास पर्याप्त समय था, लेकिन सरकार ने मुझे की गंभीरता को नहीं समझा। पांच साल का वक्त किसी नीति के निर्धारण के लिये पर्याप्त होता है। दरअसल, सरकार के रवैये से खिन्न अदालत ने केंद्र को सख्त हिदायत दी कि वह आखिरी मौके के रूप में सिर्फ आठ सप्ताह में नीति को अंतिम रूप दे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं के बाबत जवाब मांगा था, जो ऑनलाइन बेची जा रही दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के बाबत दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। साथ ही यह भी कि ये दवाइयां बिना किसी उचित नियमन के ऑनलाइन

सुधाकर आशावादी

कटु एवं व्यवहारिक सत्य यही है कि आपराधिक प्रवृत्ति के दरिन्द्रों को यदि समय से कठोर दण्ड न दिया जाए, तो दरिंदों की क्रुरता बढ़ जाती है।

समाज में बढ़ती दर्दिगी चिंताजनक

उचित संस्कारों के अभाव में ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है, जो केवल भौतिकता में विश्वास रखती है। मानवीय मूल्य जिसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। यही कारण है कि देश में दरिंदगीपूर्ण वारदातें अपनी सीमाएं पार कर रही हैं और समाज मूकदर्शक बनकर चुप्पी साधने का अभ्यर्त हो रहा है। यदि ऐसा न होता, तो नित्य ही ऐसे समाचार प्रकाश में नहीं आते, कि किसी युवती को बेरेली में रेल पटरी पर फेंक दिया गया, जहाँ उसके अंग भंग हो गए। किन्तु बालिकाओं को झूलाने के बहाने जंगल में ले जाया गया, फिर उनके साथ दरिंदगी की गई। नित्य ही ऐसी घटनाओं में वृद्धि होना केवल पुलिस और कानून व्यवस्था की खामियाँ ही नहीं गिनाना, अपितु समाज में आ रहे नकारात्मक बदलाव को भी व्यक्त करता है। कटु एवं व्यवहारिक सत्य यही है कि आपराधिक प्रवृत्ति के दरिन्दों को यदि समय से कठोर दण्ड न दिया जाए, तो दरिंदों कृता बढ़ जाती है। दिन के महिपालपुर में एक रात कैब बुक कराई गई तथा चालक बिजेंद्र शाह को ब



की तर्ती को कैब चालक के साथ दरिंदगी की वारदात ने कैब चालकों की सवारियों के प्रति विश्वसनीयता को सदेह के घेरे बभावह है। ऐसे में ३ की यात्रा को सुमान कैब व्यवस्था के स प्रश्न खड़ा हो सकता है। यात्रियों पर विश्व

माने आदमी
नाने वाली
मुख्य यह
ता है कि
वास कैसे

कभी दिल्ली की भीड़भाड़ वाली
सड़क पर किसी साक्षी का
बेरहमी से कत्तल कर देते हैं,
कभी किसी की बोटी बोटी
काटकर फ्रिज में रख देते हैं।
कभी कोई भाभी अपने प्रेमी के
साथ मिलकर अनैतिक सम्बन्ध
में विघ्न डाल रही अपनी
ननद की हत्या करा देती है।
जग्धन्य दरिंदगी की नित नई
कथाएँ प्रकाश में आती रहती
हैं। कुछ दिनों तक यह दरिंदगी
चारों में रहती है, किंतु दरिंदों
को समयानुसार दंडित न किए
जाने की कारण ही समाज में
दरिंदगी की घटनाओं की
पुनरागृहि होती रहती है। समय
की मांग है कि समाजशास्त्री,
मनोवैज्ञानिक एवं दिशानायक
इस प्रकार की क्रूरता-पूर्ण
दरिंदगी को समाप्त करने के
लिए सामूहिक प्रयास करें तथा
त्वरित न्याय करके समाज को
दरिंदों से मुक्त करने हेतु
व्यापक स्तर पर कार्रवाई करें।
भयमुक्त समाज का नारा देने
मात्र से इस समस्या का स्थाई
निदान सम्भव नहीं है।

क्यों देश को इंतजार है नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने का

की कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी दवाइयों की बिक्री पर रोक न लगाने पर ई-फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ अवमानना के कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल, इससे पहले अगस्त में कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि इस विषय पर नियमों के मसौदे पर फिलहाल विचार-विर्माश जारी है। उल्लेखनीय है कि तब मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने अंतरिम निर्देश देते हुए कहा था कि बिना वैध लाइसेंस ऑनलाइन दवाएं बेचने पर रोक के बाबत कोर्ट के 12 दिसंबर, 2018 के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर केंद्र व राज्य सरकारें अगली सुनवाई से पहले आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें। तब भी कोर्ट ने वास्तविक स्थिति पर रिपोर्ट पेश करने के लिये केंद्र सरकार से कहा था। दरअसल, याचिका दायर करने वालों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों के मसौदे को चुनौती दी थी कि जिनके जरिये औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमों में संशोधन किये जा रहे हैं। तब ऑनलाइन दवाओं की बिक्री से मरीजों की सेहत के लिये उत्पन्न खतरे की अनदेखी का भी आरोप लगा था। वहीं दूसरी ओर विगत में अदालत की कार्यवाही में सुनवाई के दौरान ऑनलाइन विक्रेताओं ने दलील दी थी कि उन्हें दवाएं बेचने के लिये लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वे तो केवल खाने की डिलीवरी करने वाले एप की तरह दवाएं डिलीवरी कर रहे हैं। जिस तरह उन एप्स को चलाने के लिये रेस्टरां के लिये लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, वैसे ही ई-फार्मेसी को भी ग्राहकों तक दवाइयां पहुंचाने के लिये लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। निस्संदेह, ऐसे किसी तर्क से सहमत होना कठिन है क्योंकि दवा की बिक्री से किसी के जीवन-मरण का प्रश्न जुड़ा है। जिसकी जीवावदेही तय हो। निश्चियत रूप से सरकार की नजर ऐसी वेबसाइटों पर होनी चाहिए जो ऑनलाइन दवा बिक्री के धंधे से जुड़ी हैं। दरअसल, ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियां ग्राहकों को भारी छूट भी देती हैं, जिसके चलते दुकानदार उनके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ऐसी वेबसाइटों को इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नियमों का पालन करने के लिये बाध्य करें। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर अस्थाई प्रतिबंध लगाया था।

अगर सब कुछ योजना के बलता रहा तो उत्तर प्रदेश के जिवर में तेजी से बन रहे नोएडा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान अगले साल मार्च के महीने में अपने सफर पर चली जाएगी। यानी अब छह से भी कम महीनों का बक बचा है, इसे शुरू होने में। पहले कहा जा रहा था कि यहां से पहली फ्लाइट साल 2024 के अंत में ही उड़ान रोखेगी। नोएडा एयरपोर्ट जितना बल्कि शुरू हो जाए उतना ही भारत आने और यहां से जाने वाले करोड़ों मुसाफिरों के लिए एक बड़ी राहत भी खबर होगी। भारत सरकार का उड्डयन एवं यूनि-मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार मिल कर कोशिश कर रहे हैं ताकि नोएडा एयरपोर्ट तक से पहले ही शुरू हो जाए। नोएडा एयरपोर्ट का तुरंत बनाना दूसरलिए भी जरूरी है ताकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आईजीआई) को यात्रियों की फीड से बचाया जा सके। इधर फीड के चलते बदइंतजामी और भ्राजकता के हालात बने रहते हैं। यात्रियों को तीन-तीन घंटे तक नाइन में लगना पड़ना आज के देन आम बात हो गई है। आईजीआई एयरपोर्ट पर साल बाद साल यात्रियों की भीड़ बढ़ती रही चली जा रही है। आज जानते हैं कि आईजीआई से प्रतिदिन दूजारा भारतीय सात समंदर पार यात्रा के लिए जा रहे हैं तो उत्तरने ही दुनिया के अलग-अलग भागों से दिल्ली आ भी रहे होते हैं। पिछले साल 2022 में तो गहर दिनिया के सभी

2002 में बंद कर दिया गया था। इसे अमेरिका में 26x11 की भयंकर घटना को देखते हुए बंद किया गया था। अब भी यहाँ से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य अति विशिष्ट हस्तियां अपने सफर पर निकलते हैं। फिर से वर्तमान में लौटेंगे। आईजीआई के शुरू होने के 20 साल के भीतर ही देश को एक नए विश्व स्तरीय एयरपोर्ट की जरूरत महसूस हुई। यह सुवृत्त है कि देश के एविएशन सेक्टर का तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। इसलिए ही ग्रेटर नोएड में जेवर एयरपोर्ट को बनाने पर निर्णय लिया गया। जान लें कि तीस हजार करोड़ रुपये की लागत से 1334 हेक्टेयर में बन रहा जेवर एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। फिलहाल यात्रियों की आवाजाही के लिहाज से आईजीआई देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एक बात और। जेवर एयरपोर्ट की टिकटे आईजीआई के मुकाबले सस्ती होंगी। ऐसा दिल्ली और यूपी में एटीएफ (एविएशन टर्बाइन प्यूल) शुल्क में अंतर के कारण सभव होगा। आईजीआई की तुलना में यात्रियों को प्रति टिकट 1,500 रुपये की बचत होगी। एविएशन मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि जिस जेवर एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा तो यहाँ से सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होने लगेगी। यहाँ से देश के विभिन्न जगहों के लिए विमान सेवा यात्रा

नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया और खेल भावना की हार

रविवार 19 नवंबर 2023 का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक हो सकता था। 1983 और 2011 की तरह टीम इंडिया क्रिकेट विश्वकप तीसरी बार जीत सकती थी। लेकिन खेल है तो हार-जीत लगी रहती है। और इस बार टीम इंडिया सभी मैचों में अपराजेय रहने के बावजूद फाइनल का मुकाबला हार गई। इसका मतलब यही है कि भारतीय टीम मजबूत है, उसके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास अकूत धन—संपत्ति है, जिससे वो सभी तरह की सुविधाएं और साधन खिलाड़ियों को मुहैया करा सकती है। यह सब होने के बावजूद भारतीय टीम ठीक—ठाक स्कोर बनाकर भी हार गई, तो इस हार को गरिमा के साथ स्वीकार करने में ही क्रिकेट की शोमा है, जिसे बद्रजनों का खेल भी कहा जाता है। लेकिन अफसोस कि इस बार क्रिकेट विश्वकप की मेजबानी करते हुए भारत में न केवल भारतीय टीम हारी, बल्कि खेल भावना भी नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में बुरी तरह मात खाती नजर आई। दरअसल खेल भावना की हार की पटकथा तो उसी दिन से लिखनी शुरू हो गई थी, जब सरदार पटेल के नाम पर बने स्टेडियम को मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम पर किया गया। इतने बड़े देश में कई और नए स्टेडियम बनाए जा सकते हैं और इनमें से किसी की भी नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हो सकता था, लेकिन तुच्छ राजनैतिक सोच के कारण नाम बदलने का जो काम लिखना शुरू हुआ है, उसका एक और उदाहरण नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में देखने मिला। 1 लाख 32 हजार लोगों को बिठाने की क्षमता वाले स्टेडियम का जब फिर से उदाघाटन हुआ था, तो यहां कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित न होकर नमस्ते टंप कार्यक्रम किया गया। खेल और

जानीति के घालमेल का यह मोदीयुगीन उदाहरण था। इसके बाद ऐसी कई और मिसालें देखने मिली हैं। महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन शोषण की न केवल शिकायत की, बल्कि उसके लिए अदालत तक से गुहार लगा दी, जंतर-जंतर पर लंबांगरना—प्रदर्शन किया। लेकिन जिस ब्रजभूषण शरण सिंह पर मौखितरु आरोप हैं, वो आज भी संसद में मौजूद है और पीड़ित खेलाड़ी इंसाफ की बात जोह रहे हैं। इन खिलाड़ियों के समर्थन में संसद में ही मौजूद नामवीन खेलाड़ी पी टी उषा ने कोई आवाज नहीं उठाई, उल्टा उन्हें नसीहत दे दी। लेकिन भारत का छहला विश्वकप दिलाने वाले कपिल देव ने महिला खिलाड़ियों के हक में आवाज उठाई थी, तो वह इस बार नरेन्द्र मोदी स्टेडियम महीने पहुंच पाए। कपिल देव ने पीड़िया से बात करते हुए बताया कि वे तो चाहते थे कि उनके साथ पहली बार विश्वकप उठाने वाली पूरी टीम फाइनल मुकाबले देखने पहुंचती, लेकिन वीसीसीआई शायद इतने जरूरी कामों में यस्त है कि उन्हें फाइनल मुकाबला देखने के लिए आमंत्रित ही हैं। उन्हीं किया गया। वैसे ये देखना रोचक है कि कपिल देव के करेदार को सिनेमा में उतारने वाले रणवीर सिंह अपनी पत्नी प्रिपिका पादकोण के साथ नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे।

A photograph showing a group of Indian cricket players in blue jerseys, including Virat Kohli, huddled together in a celebratory huddle during a match. The players are wearing blue caps and jerseys with numbers like 45, 9, and 22. The background is blurred, showing stadium lights and spectators.

राजनेता भी शामिल हैं, नरेन्द्र मोदी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। अगर इस हार का ठीकरा मोदी सरकार की खेल नीति की वजह से फोड़ा जाता, तब भी बात समझ में आती। मगर कई लोगों ने नरेन्द्र मोदी को लिए पनाई शब्द का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पर भी यह शब्द ड्रैग करने लगा। यह सरासर खेल भावना के विरुद्ध बात है। खेल से तो शारीरिक और मानसिक तंदरुस्ती अच्छी होती है, इसमें अंधविश्वास जैसी बीमारी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी शिकायत का कारण हो सकती है, क्योंकि जब देश में मणिपुर की गंभीर समस्या है, जब उत्तरकाशी की सुरंग में आठ दिनों से मजदूर फसे हुए हैं, ऐसे संकटों के बीच प्रधानमंत्री मोदी खेल का आनंद लेने के लिए पहुंचे, यह सही बात नहीं है। श्री मोदी से इस बात की भी शिकायत की जा सकती है कि उनके शासन में देश ये कैसे मुकाम पर आ पहुंचा है, जहां धर्म और राष्ट्रवाद के उन्नाद में हम मेहमाननवाजी और सामाज्य शिक्षावार भी भूलते जा रहे हैं। इसी स्टेडियम में पिछले महीने पाकिस्तान के साथ हुए मुकाबले में दर्शकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर भारत की अतिथि परंपरा को ठेस पहुंचायी थी। उसके बाद रविवार को आस्ट्रेलियाई टीम के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। उनकी जीत और अच्छे प्रदर्शन पर वाहवाही का जश्न सन्नाटा पसरा रहा। लाख की क्षमता गाले स्टेडियम में जब जिजेता टीम विश्वकप उठा रही थी तो उसकी हौसलाअफजाई के लिए उंगलियों पर यिने जाने लायक दर्शक मौजूद थे, खुद प्रधानमंत्री आस्ट्रेलियाई कपतान पैट कमिस को मंच पर ट्राफी के साथ अकेले छोड़कर चले गए।

जारी हुआ धर्मपरिवार का कार्यक्रम कैलेण्डर आजीवन संरक्षक ने सौपी जिम्मेदारियों

पृष्ठांजली टुडे

रीवा। पारिवारिक दायित्वों, समय के अभाव के चलते समझे वर्ष भर होने वाले धार्मिक उत्सवों को एक शाखा द्वारा मानाया जाना पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है और कोई ना कोई कमी रह जाती है, इसलिये हिन्दू उत्सव समिति धर्मपरिवार की सभी शाखायें मिलजुलकर अपसी तालमेल बनकर अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्यों का निर्वहन करेगी। इस आशय को लेकर धर्मपरिवार के संस्थापक आजीवन संरक्षक नारायण डिगवानी ने 2024 का वार्षिक कैलेण्डर जारी किया है, जिसमें सभी शाखाओं को जिम्मेदारियों सौंपी गई है, जिनको वो अपने संसाधनों एवं परिकल्पना से स्वतंत्र रूप से संपादित करेगी। साथ ही एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखेंगे। धार्मिक उत्सव मनाने वेरिश शाखा मकर संक्रान्ति, शिवात्री, स्वतंत्रता दिवस, नवदुर्गा गवरा, श्री राम धर्म विजय शोभा यात्रा में सहभागिता करेगी। युवा शाखा रामनवमी, होली, गणेशत्सव, दीपाली का दायित्व संभागनीयी। मिलिया शाखा को बसंत पंचमी, रक्षाधूधन और जन्माष्टी मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा वर्ष भर महापुरुषों की जयतियों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक, रचनात्मक कार्यों में स्वैच्छिक अधिसूचना परिचय शाखा पदाधिकारी दे सकते हैं। सभी शाखायें अपस में सहयोग और भाइचारे के साथ कार्य करेगी, धर्मपरिवार नगर में धार्मिक उत्सवों की परम्परा को जारी रखना चाहता है।

सुमित मांजवानी
युवा अध्यक्ष
हिन्दू उत्सव समिति धर्मपरिवार रीवा (म०प्र०)

पूरी सावधानी और पारदर्शिता से मतगणना करें - जिला निर्वाचन अधिकारी



रीवा। जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना तीन दिसंबर को प्रातः 8 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में आरंभ होगी। मतगणना के लिए विधानसभावाक कक्ष निर्धारित किए गए हैं। मतगणना के लिए गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक तथा जानकारी प्रेषक तैनात कर दिए गए हैं। इनका एक दिवसीय प्रशिक्षण शासकीय विधि महाविद्यालय के विभिन्न कक्षों में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में मतगणना के संबंध में निर्देश देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि मतगणना पूरी सावधानी तथा पारदर्शिता से करें। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप मतगणना करें। मतगणना के दौरान अपना व्यवहार संयमित रखें। गणना प्रारंभ करने के पूर्व प्रत्येक मतगणना एजेंट को वोटिंग मशीन तथा उपकरी सील दियाएं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी की गणना होगी। डाक मतपत्रों के लिए अलग से दल तैनात होगा। डाक मतपत्रों के साथ दिए गए घोषणा पत्र में मत पत्र क्रमांक ठीक होने तथा उत्तिष्ठान अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही उसे मान्य करें। घोषणा पत्र में मत देवे वाले कमीशरी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मतगणना की निरागरी के लिए माझको प्रेषक भी तैनात रहेंगे। प्रशिक्षण देते हुए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ. सौरभ सोनवाने ने कहा कि वोटिंग मशीन से मतदान होने के कारण मतगणना में कोई कठिनाई नहीं होगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मशीन के परिणाम खण्ड से कुल मत तथा उम्मीदवार को मिले मतों को देखकर निर्धारित प्रपत्र में अंकित करें। गणना एजेंटों को भी प्रत्येक चक्र में उम्मीदवार को मिले मतों की जानकारी दें। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में गणना एजेंट के हस्ताक्षर भी प्रत्येक चक्र के परिणाम में कारण। मतगणना के लिए निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. अमरजीत सिंह तथा अन्य मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफीसर के स्तर पर की जाएगी। वोटिंग मशीन में गणना करने के पूर्व उसके सभी एडेस ट्रेग तथा सील का निरीक्षण करें। मशीन में अंकित कुल मत की जानकारी मतगणना एजेंटों को दें। प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की जानकारी भी उनके उम्मीदवारों को देते हुए निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करें। इसमें एजेंट के हस्ताक्षर भी कारण। गणना के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक से तक टेबिलों होंगी। पहली टेबिल पर मतदान क्रमांक एक की मशीन आएगी। इसी तरह मतगणना केन्द्र के पृथक करने के लिए एडेस ट्रेग तथा सील का निरीक्षण करें। इस सबध में निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि श्री सौरभ कुमार निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात रखने के बाद प्रत्येक चक्र के लिए जिले के कर्मचारी आवाले वाले लोगों द्वारा निरीक्षण करें। इनके बाद निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि मतगणना पूरी सावधानी तथा पारदर्शिता से करें। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप मतगणना करें। मतगणना के दौरान अपना व्यवहार संयमित रखें। गणना प्रारंभ करने के पूर्व प्रत्येक मतगणना एजेंट को वोटिंग मशीन तथा उपकरी सील दियाएं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी की गणना होगी। डाक मतपत्रों के लिए अलग से दल तैनात होगा। डाक मतपत्रों के साथ दिए गए घोषणा पत्र में मत पत्र क्रमांक ठीक होने तथा उत्तिष्ठान अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही उसे मान्य करें। घोषणा पत्र में मत देवे वाले कमीशरी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मतगणना की निरागरी के लिए माझको प्रेषक भी तैनात रहेंगे। प्रशिक्षण देते हुए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ. सौरभ सोनवाने ने कहा कि वोटिंग मशीन से मतदान होने के कारण मतगणना में कोई कठिनाई नहीं होगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मशीन के परिणाम खण्ड से कुल मत तथा उम्मीदवार को मिले मतों को देखकर निर्धारित प्रपत्र में अंकित करें। गणना एजेंटों को भी प्रत्येक चक्र में उम्मीदवार को मिले मतों की जानकारी दें। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में गणना एजेंट के हस्ताक्षर भी कारण। मतगणना के लिए निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. अमरजीत सिंह तथा अन्य मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफीसर के स्तर पर की जाएगी। वोटिंग मशीन में गणना करने के पूर्व प्रत्येक एडेस ट्रेग तथा सील का निरीक्षण करें। इनके बाद निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि मतगणना पूरी सावधानी तथा पारदर्शिता से करें। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप मतगणना करें। मतगणना के दौरान अपना व्यवहार संयमित रखें। गणना प्रारंभ करने के पूर्व प्रत्येक मतगणना एजेंट को वोटिंग मशीन तथा उपकरी सील दियाएं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी की गणना होगी। डाक मतपत्रों के लिए अलग से दल तैनात होगा। डाक मतपत्रों के साथ दिए गए घोषणा पत्र में मत पत्र क्रमांक ठीक होने तथा उत्तिष्ठान अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही उसे मान्य करें। घोषणा पत्र में मत देवे वाले कमीशरी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मतगणना की निरागरी के लिए माझको प्रेषक भी तैनात रहेंगे। प्रशिक्षण देते हुए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ. सौरभ सोनवाने ने कहा कि वोटिंग मशीन से मतदान होने के कारण मतगणना में कोई कठिनाई नहीं होगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मशीन के परिणाम खण्ड से कुल मत तथा उम्मीदवार को मिले मतों को देखकर निर्धारित प्रपत्र में अंकित करें। गणना एजेंटों को भी प्रत्येक चक्र के परिणाम में कारण। मतगणना के लिए निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. अमरजीत सिंह तथा अन्य मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफीसर के स्तर पर की जाएगी। वोटिंग मशीन में गणना करने के पूर्व प्रत्येक एडेस ट्रेग तथा सील का निरीक्षण करें। इनके बाद निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि मतगणना पूरी सावधानी तथा पारदर्शिता से करें। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप मतगणना करें। मतगणना के दौरान अपना व्यवहार संयमित रखें। गणना प्रारंभ करने के पूर्व प्रत्येक मतगणना एजेंट को वोटिंग मशीन तथा उपकरी सील दियाएं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी की गणना होगी। डाक मतपत्रों के लिए अलग से दल तैनात होगा। डाक मतपत्रों के साथ दिए गए घोषणा पत्र में मत पत्र क्रमांक ठीक होने तथा उत्तिष्ठान अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही उसे मान्य करें। घोषणा पत्र में मत देवे वाले कमीशरी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मतगणना की निरागरी के लिए माझको प्रेषक भी तैनात रहेंगे। प्रशिक्षण देते हुए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ. सौरभ सोनवाने ने कहा कि वोटिंग मशीन से मतदान होने के कारण मतगणना में कोई कठिनाई नहीं होगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मशीन के परिणाम खण्ड से कुल मत तथा उम्मीदवार को मिले मतों को देखकर निर्धारित प्रपत्र में अंकित करें। गणना एजेंटों को भी प्रत्येक चक्र के परिणाम में कारण। मतगणना के लिए निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रभारी डॉ. अमरजीत सिंह तथा अन्य मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में बताया गया कि डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग आफीसर के स्तर पर की जाएगी। वोटिंग मशीन में गणना करने के पूर्व प्रत्येक एडेस ट्रेग तथा सील का निरीक्षण करें। इनके बाद निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि मतगणना पूरी सावधानी तथा पारदर्शिता से करें। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप मतगणना करें। मतगणना के दौरान अपना व्यवहार संयमित रखें। गणना प्रारंभ करने के पूर्व प्रत्येक मतगणना एजेंट को वोटिंग मशीन तथा उपकरी सील दियाएं। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी की गणना होगी। डाक मतपत्रों के लिए अलग से दल तैनात होगा। डाक मतपत्रों के साथ दिए गए घोषणा पत्र में मत पत्र क्रमांक ठीक होने तथा उत्तिष्ठान अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही उसे मान्य करें। घोषणा पत्र में मत देवे वाले कमीशरी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मतगणना की निरागरी के लिए माझको प्रेषक भी तैनात रहेंगे। प्रशिक्षण देते हुए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ. सौरभ सोनवाने ने कहा कि वोटिंग मशीन से मतदान होने के कारण मतगणना में कोई कठिनाई नहीं

